



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 150 राँची, सोमवार 17 चैत्र 1936 (श०)
7 अप्रैल, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

27 मार्च, 2014

संख्या-5/आरोप-1-654/2014 का०-3081--श्री सत्यप्रकाश, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के विरुद्ध वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के लिए दीनदयाल आवास योजना के योजना पंजी में सुरेश भुईयों के नाम का उल्लेख नहीं रहने के बावजूद उनके नाम से राशि की निकासी की गई; श्री सुरेश भुईयों से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेख की प्रति में योजना सं० को काट कर अपठनीय बना दिया गया; चेक सं०- 445992 दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 के द्वारा 12,500/- नगद के रूप में बैंक द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को भुगतान किया गया आदि आरोप प्रपत्र- 'क' में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०- 2098 दिनांक 11 अप्रैल, 2008 द्वारा श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल,

हजारीबाग-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-15, दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-3 एवं 4 प्रमाणित प्रतिवेदित किये गए। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-11210, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 द्वारा श्री सत्य प्रकाश पर निन्दन एवं तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके विरुद्ध श्री सत्य प्रकाश द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका W.P.(s) No.-478/2013-सत्य प्रकाश बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2013 को आदेश पारित किया गया है। न्यायादेश का व्चमतंजपअम चंतज निम्नवत् है:-

"In view of aforesaid discussion the impugned order dated 1 October, 2012 is quashed. The matter is remitted to the disciplinary authority for passing a fresh order, after affording opportunity to the petitioner for making his representation."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री सत्य प्रकाश के विरुद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प सं0-11210, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।
